operation. In addition, work on the following lignite based power projects is in progress:

(i) Neyveli Second Mine Cut Stage-II Unit 4 (210 MW).

(ii) Neyveli Second Mine Cut Stage-I Zero Unit (1x210 MW).

(iii) Kutch Lignite Extension Unit-3 (70 MW).

Coal-gas based power plant at Dankuni, West Bengal

964. SHRI AJIT P. K. JOGI:
SHRI CHHOTUBHAI PATEL:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up a coal-gas based power plant at Dankuni, West Bengal;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether any such projects are envisaged at the coal pitheads in Madhya Pradesh, Bihar and Orissa?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Capacity utilisation of Hydel Plants

965. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) what was the capacity utilisation percentage of hydroelectric power plants in the country during the last three years and what is the expected percentage during the current financial year;

(b) what specific steps are being taken to improve the capacity utilisation of power plants;

(c) whether there is any plant to take over some power plants from State sector to Central Sector; and

(d) if so, the details thereof and also the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) The capacity utilisation of hydro-electric stations during the last three years and during 1992-93 (April 1992 to January 1993), is given below:—

Year	Installed Capacity in the beginning of the year (MW)	Design Energy MU	Actual Generation MU	
1992-93 (4/92 to 1/93) . . .	19191.62	56242	59576	105.9
1991-92	18752.62	65909	72599	110.2
1990-91	18307.12	65456	71535	109.3
1989-90	17797.22	64828	61996	95.

Note: The hydro generation during last three years is more than the designed energy due to gr availability of water.

(b) To improve capacity utilisation of hydro power plants, a programme has been formulated by CEA for Renovation, Modernisation and Uprating (RM&U) of power stations. Under this programme 54 schemes with total installed capacity of 9656 MW (211 Units) have been identified. The benefits expected after implementation of RM&U works of these 54 schemes are 884 MW and 1203 MW of additional energy per annum by way of recovery of derated capacity, uprating and improvement in availability and reliability of power stations for optimum utilisation of their plant capacity.

(c) and (d) No Sir.

राजस्थान में विद्युत आपूर्ति

965. **श्री शिव चरण सिंह :** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्युत का राज्यवार कुल कितना-कितना उत्पादन तथा उपभोग किया जाता है ;

(ख) उत्पादन और मांग के वर्तमान अंतर को दूर करने के लिये क्या-क्या कदम उठाये जाने का विचार है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार राजस्थान की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने के प्रति उदासीन है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) राजस्थान में विद्युत की मांग को कब तक पूरा कर दिया जायेगा; और

(ङ) क्या केन्द्र सरकार राज्य के विकास हेतु राजस्थान को सस्ती दरों पर अपेक्षित विद्युत प्रदान करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू) : (क) अप्रैल–जनवरी, 93 के दौरान विद्युत सप्लाई की स्थिति का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **(नीचे देखिये)** ।

(ख) बिजली की उपलब्धता में सुधार करने हेतु किये जा रहे विभिन्न उपायों में नई विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना, अल्पावधि में तैयार की जा सकने वाली परियोजनाओं को कार्यान्वित करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करना, पारेषण एवं वितरण संबंध हानियों को कम करना, मांग प्रबंधन तथा ऊर्जा संवर्धन संबंधी उपायों को कार्यान्वित करना, अतिरेक ऊर्जा वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को बिजली का अंतरण करना आदि शामिल है ।

(ग) केन्द्र सरकार समय-समय पर राजस्थान की उन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करती रही है जिन्हें तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य पाया गया तथा जिनके लिये अपेक्षित लिंकेज व स्वीकृतियां तथा आवश्यक वित्तीय व्यवस्थाएं प्राप्त हो गई थी ।

(घ) आठवीं योजना के अन्त तक भी राजस्थान द्वारा बिजली की कमी का सामना किये जाने की संभावना है यद्यपि आठवीं योजना अवधि के दौरान राजस्थान राज्य में 673 मेगावाट की नई उत्पादन क्षमता चालू किये जाने का प्रस्ताव है ।

(ङ) केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्र से लाभभागी राज्यों को बिजली की सप्लाई निर्धारित केन्द्रीय फार्मूले के अनुसार तथा एक समान उत्पादन लागत पर की जाती है ।